SHRI PILOO MODY : Unfortunately, parliamentary procedures ..

MR. SPEAKER : No, please Mr. Pandey.

SHRI P. K. DEO : I snbmit item No. 19 should have been taken now.

MR. SPEAKER : First you ask for extension of time and then you deprive the other Member of his right.

We will now take up the half-hour discussion which will be over by 6.30 and then we take up the discussion under Rule 193 for an hour. As we are at the fag end of the session. I hope you won't mind sitting a little late.

Mr. Pandey.

---

18 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION RE: CRASH PROGRAMME FOR PROVIDING EMPLOYMENT TO UNEDUCATED UNEMPLOYED

श्री एन० एन० पाण्डे (गोरखपुर) : श्री रण बहादुर सिंह जी ने एक प्रश्न किया था 1597, 25 मई को और यह 50 करोड़ रुपयां जो क्रैश प्रोग्राम था उसके सम्बन्ध में था। कुछ भ्रांतियां रह गई थी जिनकी मंत्री जी ने सफाई नहीं दी। यह नही बताया कि उस पैसे का कौन कौन से प्रदेशों में और किन किन प्रोजैक्ट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। अठारह प्रदेशों में से कुछ एक के नाम लिये गये थे।

मैं आपका ध्यान बेकारी की जो समस्या है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। पहली योजना में 5.3 लाख आदमी बेकार थे...

[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*]

दूसरे प्लान में उनकी संख्या बढ़कर 7.1 लाख हो गई। तीसरे प्लान में 9.6 लाख हो गई और चौथे प्लान में वह बढ़ कर 12.6 लाख हो गई। ज्यों ज्यों योजनायें बनती गई त्यों-त्यों बेरोजगारों की संख्या भी बढती गई और बढ़ती जा रही है। हिन्दुस्तान के पांच लाख गांवों में आज किस तरह की परिस्थिति है? वहां जो लेबर है, जो एग्रिकल्चरल लेबर है, वह बेकार है। उसको रोजगार की जरूरत है। हमने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रोग्राम बनायेंगे और उस प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों मे सड़कें तथा दूसरे कार्य करेंगे ताकि लोगो को वहा पर काम मिले। हमने कहा था कि हम ऐसे कार्यक्रम हाथ मे लेंगे जिनसे एजुकेटिड तथा अनएजुकेटिड दोनो तरह के लोगों को काम मिले। वह एक ऐसी बात थी जिससे सारे देश के लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई और खास तौर से गरीब लोगों में दौड़ गई।

इस वर्ष जो क्रैश प्रोग्राम पचास करोड़ रुपये का बनाया गया था आज तक मै कह सकता हूं कि किसी भी प्रदेश में चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, उस पर काम नहीं हुआ। आपने कहा है कि दस प्रतिशत हमने "ईयरमार्क" कर दिया है जो सामान होगा उसकी परचेज के लिए। मैंने अपने जिले गोरखपुर में वहां के जिलाधीश महोदय से मेरी बात हुई है और इस प्रोग्राम के बारे में मीटिंग हुई। मैंने उनसे जानना चाहा कि आप क्या कार्यक्रम अपनाने जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सुपरवाइजरी काम के लिए, जिस काम को चलाया जा सकता है, उसकी देखभाल की जा सके इसके लिए सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया। इस बात को मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि बहुत से प्रदेशों ने अपने प्राजैक्ट्स नहीं भेजे हैं। इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि उनको सैंक्शन नहीं किया गया हैं। इस तरह से कैसे आप बेकारी की समस्या को हल करेंगे, कैसे हमने देश की जनता के साथ जो वादे किये हैं उनको पूरा कर पायेंगे।

मैं कैटेगोरिक जवाब और स्पेसेफिक जवाब

मंत्री महोदय से अपने प्रश्न का लेना चाहता हू। मैं प्रश्न दोहरा देता हूँ। भिन्न-भिन्न प्रदेशो मे कौन-कौन से प्राजैक्ट्स पर आपकी आशानुसार काम किया जा रहा है? कुल कितने लोग वहा पर लगे हुए है? कितने एम्प्लायड है और कितने अनएम्प्ल यड है यह भी बताया जाए? यह सब जानकारी दी जाए ताकि पता चल सके कि सही तरीके से प्रदेशो की सरकारो ने भारत सरकार की नीति को पक्के तरीके म पकडा है और वे चाहती है कि बेकारी की समस्या हल हो।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : बेकारी दूर करने के सम्बन्ध मे क्रैश प्रोग्राम जो सरकार ने बनाया है उसी के सिलसिले मे बहस चल रही है। जो सवाल था उसका जो जवाब मन्त्री महोदय ने दिया उससे सदन को सतोष नही हुआ। सरकार को अभी तक यह भी पता नही कि हमारे देश मे कितने बेकार हैं। तीन चार बाते मै आपके सामने रखना चाहता हूँ और आशा करता हू कि उनका उत्तर दिया जायेगा। यह हो सकता है कि क्रैश प्रोग्राम से अलग भी बाते हो जाये। लेकिन आप मेरे प्रश्न सुन लीजिये।

क्या यह सच है कि योजना मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने 28 मई 1970 को जब वह मत्री नही थे केन्द्र और राज्यो के काग्रेस नेताओ के सम्मेलन मे 1985 तक बेकारी की समस्या को हल करने की घोषणा की थी?

क्या यह भी सच है कि उन्होने उक्त सम्मेलन मे 1972 तक बकार इन्जीनियरो, डाक्टरो, कृषि सनातनो तथा 1975 तक सभी डिग्रीधारी बेकार व्यक्तियो को काम देने की घोषणा की थी? यदि हा तो क्या उन्होने योजना मन्त्री के पद पर नियुक्त होने के बाद इस प्रकार की कोई योजना तैयार की है और की है तो उसका ब्यौरा क्या है?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या यह सच है कि सरकार ने देश मे बेकारो की सख्या का पता लगाने के लिए किसी समिति का गठन किया है यदि हा तो उसकी रिपोर्ट सरकार को कब तक मिलने की आशा है और क्या सरकार ने उसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और अगर की है तो वह क्या है?

क्या सरकार बकारो को काम या बेकारी भत्ता देने की माग को स्वीकार करने के लिए तैयार है, यदि नही तो क्या नही?

क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने बेकार इन्जीनियरो को काम देने की कोई योजना तैयार की है, यदि हा, तो उसका ब्यौरा क्या है?

क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने बेकार सनातको को सिचित भूमि, इरिगेटिड लैन्ड देने की कोई योजना तैयार की है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है और उसकी क्रियान्विति की क्या स्थिति है?

राज्यो म क्रैश प्रोग्राम जिसकी चर्चा अभी की गई है के इम्प्लेमेटेशन की स्थिति क्या है? अभी तक किन-किन राज्यो ने उसको किस किस तरीके से लागू करने की कोशिश की है और वे आज कहा तक पहुचे है और आगे ने कहाँ तक पहुचना चाहते है?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : बहुत ज्यादा महगाई बढ गई है। साथ ही जो बेकार है उनमे मौसमी बेकार, आशिक बेकार, पूरे बेकार, अर्ध बेकार हमारे देश मे कितने है क्या इसकी आपने कभी छानबीन की है? क्रैश प्रोग्राम मे आप किन लोगो को क्या जो अर्ध बेकार है, उनको लगाना चाहते है, जो मौसमी बेकार होते है उनको लगाना चाहते है या जो पूरे बेकार है, उनको लगाना चाहते हैं, इस पर आप प्रकाश डाले।

जिन घरो मे कोई कमाने वाला है, उन लोगो के घरो मे अगर कोई बेकार है तो क्या उसको भी आप काम मे लगायेगे? जिस घर से इनकम टैक्स दिया जाता है जिसका बाप या उसके कुटुम्ब मे कोई सदस्य इनकम

[श्री मूलचन्द डागा]

टैक्स देता है क्या उस कुटुम्ब में अगर कोई बेकार है तो उसको भी आप नौकरी मे लगायेंगे ? क्या उसको भी आप मजदूरी देंगे ?

जिसके पास कोई काम धंधा है, चाहे वह काश्तकारी का है या कोई दूसरा धधा है, उसके घर में अगर कोई बेकार है तो उसको आप नौकरी देंगे ?

सरकार एक जिले मे एक हजार आदमियो को काम देना चाहती है। मै यह जानना चाहता हूं कि इस बात की जाँच कौन करेगा कि किन एक हजार आदमियो को काम दिया जाये। आज हर एक जिले मे लाखो की सख्या में बेकार है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एक जिले मे एक हजार आदमियो को काम देने के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगो को और उन लोगों को, जिनके घर मे कमाने का कोई साधन नहीं है, प्रेफरेन्स दिया जायेगा।

मैं यह भी जानना चाहता हू कि इस क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत जो रोड्स बनाई जायेगी, या जो लघु सिंचाई योजनाये शुरू की जायेगी, क्या उनके सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों या जिला परिषदो का भी सहयोग लिया जायेगा या नही। क्या इन रोड्स और योजनाओ को पूरा कर दिया जायेगा या अधूरा छोड़ दिया जायेगा ? क्या सरकार इन योजनाओ के बनाने में लोगो के प्रतिनिधियो, पचायत समितियों, जिला परिषदो, एम० पीज० और एम० एल० एज० का सहयोग लेती है या वह स्वयं ही इन योजनाओ को बनाती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : सभापति महोदय, क्रैश स्कीम फार रूरल एम्प्लायमेंट के सम्बन्ध मे पहले इस सदन में कुछ प्रश्न पूछे गये थे और आज स्पष्टीकरण के लिये कुछ और सवाल हमारे सामने आये हैं।

माननीय सदस्य, श्री नरसिंह नारायण पांडे, ने पूछा है कि सरकार इस क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत पचास करोड़ रुपया स्टेटवाइज कैसे खर्च करना चाहती है इस प्रोग्राम में कौन-कौन सी योजनाये ली जानी हैं क्या स्टेट गवर्नमेंट्स से कान्टिजेंसी फंड के लिए पूछा गया है या नही और क्या सुपरवाइजरी कामों के लिये पैसा रखा गया है या नही।

स्टेट-वाइज जो पैसा दिया गया है, उसकी सूची बहुत लम्बी है। लेकिन हमने यह सिद्धात रखा है कि हर जिले के लिए 12.50 लाख रुपया दिया जाये। लेकिन बिहार और कुछ दूसरे प्रदेशो मे कुछ ऐसे भी जिले है, जिनकी जनसख्या बहुत अधिक है। उनको इसके अलावा और पैसा भी दिया गया है। स्टेट को यह जो अतिरिक्त पैसा दिया गया है, उसका ब्रेक-अप इस प्रकार है--केरल : 34 लाख, उडीसा : 20.50 लाख, तमिलनाडु : 103 लाख, उत्तर प्रदेश : 4 लाख, वैस्ट बगाल : 99 लाख, बिहार : 245.50 लाख और आन्ध्र प्रदेश : 56.50 लाख।

नागालैंड और दादरा नगर हवेली, इन दो स्टेट्स से स्कीमे आई है। बाकी सब स्टेट्स से स्कीमे आ गई है। कुछ स्टेट्स ऐसी है, जिनके सब जिलो की स्कीमे नही आई है— बहुत से जिलो की स्कीमे आ गई है, लेकिन एक दो जिलों की नही आई हैं। इस प्रकार देश भर मे 355 जिलों मे से 336 जिलो की स्कीमें आ गई है और 19 जिलों के बारे में प्रोपोजल्ज नही आई है। इन 336 जिलो मे से 317 जिलो की स्कीमे सेंक्शन हो गई है और पैसा रिलीज कर दिया गया है। 7 जिलों की प्रोपोजल्स को प्रोसेस कर लिया गया है और उनकी सेंक्शंज इस्यू की जा रही है। बाकी 12 जिलो की सेंक्शन्ज भी जल्दी इस्यू कर दी जायेंगी। कलकत्ता और बम्बई वगैरह शहर इस स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते है। (व्यवधान)

सारे देश में जो स्कीमें चालू की गई हैं,

उनमे 60 प्रतिशत रुपया सड़के बनाने पर, 25 प्रतिशत माइनर इरिगेशन की योजनाओ पर और 15 प्रतिशत रुपया एफारेस्टेशन, सायल कांजरवेशन और लंड रिक्लेमेशन वगैरह पर खर्च होगा।

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : मै यह जानना चाहता हूं कि जिले में जो 12 50 लाख रुपया खर्च होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए रुपया उसी मे से खर्च किया जायेगा या सरकार अपनी तरफ से देगी।

श्री शेर सिंह : सुपरवाइजरी स्टाफ तो स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टैरीटरीज की सरकारों और सम्बद्ध डिपार्टमेंट्स की तरफ से दिया जायेगा। हमने 12.50 लाख रुपये में मे 20 परसेट, अर्थात् 2.50 लाख रुपया एक्विपमेंट के लिये रखा है। 2.50 लाख रुपये मे मे जहा जरूरी हो, 3 परसेट रुपया स्किल्ड लेबर के लिये खर्च किया जा सकता है। बाकी 10 लाख रुपया अनस्किल्ड लेबर, मिट्टी डालने और एफारेस्टेशन वगैरह के काम के लिए खर्च होगा।

8 स्टेट्स मे यह काम चालू हो गया है। 5 स्टेट्स ने कहा है कि वे बहुत जल्दी चालू करने वाली है। एफारेस्टेशन का काम तो बारिश के दिनो मे हो सकता है, लेकिन सड़के बनाने का काम और माईनर इरिगेशन का काम इन दिनों में नहीं हो सकता है। उम्मीद है कि बारिशो के बाद यह काम सब स्टेट्स मे चालू हो जायेगा। यह काम मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मैसूर, वैस्ट बंगाल, बिहार उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान मे शुरू हो चुका है। हमारे अधिकारी इन स्टेट्स को विजिट भी कर चुके है।

श्री एन० एम० पांडे : जिन सड़कों का काम शुरू हो चुका है, मंत्री महोदय उनमें मे एक सड़क का नाम बता दे।

श्री शेर सिंह : माननीय सदस्य, श्री रामावतार शास्त्री, ने जो प्रश्न पूछे है, उनमें से कुछ ऐसे है, जिनका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नही है। जहां तक बेकार लोगों की संख्या का सम्बन्ध है, उसकी जांच करने के लिये श्री बी० भगवती की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी बैठी है। वह कमेटी जांच कर रही है। लेकिन हम उसकी रिपोर्ट की इन्तजार नही कर रहें हैं। पता नहीं, उसमें कितना समय लगेगा। इसलिये यह काम पहले ही शुरू कर दिया गया है और इसी वजह से इस का नाम क्रैश प्रोग्राम रखा गया है। अगर किसी समस्या का समाधान करना हो, तो यह जरूरी है कि काम यथा शीघ्र शुरू कर दिया जाये। हमने यह सोचकर काम शुरू किया कि हम देहात के अन्दर जो इतना अनएम्प्लायमेंट है उसको दूर करने के लिये कोई बात सोचे। शास्त्री जी ने बहुत सारी बातें तो पढ़े लिखे लोगो, डिग्री होल्डर्स और इन्जीनियर्स वगैरह के लिए पूछी ..

श्री रामावतार शास्त्री : राजस्थान में जमीन के लिये मैंने पूछा।

श्री शेर सिंह : राजस्थान मे जो डिग्री होल्डर्स है और पढ़े लिखे लोग अनएम्प्लायड है उन्ही को जमीन देने के बारे मे आपने पूछा। उसका इससे सम्बन्ध नहीं है। यह स्कीम तो विशेष रूप से गांवों के अन्दर उन अनस्किल्ड लोगो के लिए है जो साल के दस महीने या 8 महीने बेरोजगार रहते है। एक प्रश्न पूछा श्री डागा जी ने इसकी जांच के सम्बन्ध में तो इस स्कीम मे यह विशेषता है कि इसमें कामों का भी चुनाव करते है। काम ऐसे होने चाहिए कि जिसमे परमानेंट असेट्स तैयार हो, पैसा बरबाद न हो। सड़कें बनायेगे तो अधूरी नहीं छोड़ देंगे, उसे पूरा करेंगे। यह फैसला किया है कि सड़के पक्की बनानी है। यह नही कि मिट्टी डाली और वह बह गई। ऐसा काम करना है जिसमें पैसा बरबाद न हो।

[श्री शेर सिंह]

दूसरी बात यह है कि जितने भी काम हम चुने, लोगो का चुनाव करने मे एक हजार आदमी जो रखने है उसमे एक हजार आदमियो पर हम इनसिस्ट नही करेगे क्योकि कई जगह अभी काम शुरू नही हुआ। तो उसमे मैन-डेज का हमने ध्यान रखा है। ढाई लाख से तीन लाख मैन-डेज हो जाने चाहिये। तीन चार महीने कही काम होता है तो एक हजार की जगह 2 हजार भी हो सकते हैं, लेकिन मैन-डेज इतने पूरे हो जाने चाहिए।

कुछ लोगो ने कहा कि इसमे इनकम टैक्स देने वाले लोग भी आ जायेगे। तो इनकम टैक्स देने वाला ऐसा कोई नही है जो मिट्टी की टोकरी उठाकर सडक के ऊपर डालता फिरे। इसमे तो वही आदमी जायेगा जिस बेचारे को कोई काम मिलता नही है। और इसमे इस बात का ध्यान हमने रखा है कि उन्ही लोगो को चुने जो बेरोजगार है। जिन लोगो के पास रोजगार बिलकुल नही है या बहुत कम है कभी मिलता है कभी नही मिलता है, जिनकी आर्थिक अवस्था बहुत खराब है और जिनके परिवार मे कोई आदमी रोजगार मे नही है पूरी तरह स उन लोगो को विशेष ध्यान मे रखेगे। इसीलिए इसमे समय भी लगा। यह एतराज होता है कि चार महीने लग गये, काम क्यो नही शुरू किया क्योकि कुछ स्टेट्स मे ही काम अभी शुरू हुआ है, कुछ से नही शुरू हुआ है, तो इसमे यह कठिनाई थी कि हमको एक तो काम का चुनाव करना था कि फला-फला काम होने चाहिये जिसमे परमानेंट असेट्स तैयार हो और पैसा बरबाद न हो। उसकी गाइड लाइस हमने उनको दी। दूसरी बात यह है कि उसके एस्टीमेट्स भी ठीक ढग से तैयार हो ताकि यह न हो कि इसमे पैसा बरबाद हो। और फिर यह कि इसमे लोगो का चुनाव भी कराना है कि किन लोगो को यह काम दिया जाय। ठेकेदारो से यह काम न ही कराना है। वैसे यह काम तो सरकार ठेकेदारो को सौप देती तो भी हो जाते, पक्की सड़क भी वह बना सकते है, सारे काम कर सकते है। लेकिन हम यह नही चाहते कि उनको यह काम मिले जिसमे वह कही से लेबर ले आये और उसको एक्सप्लायट करे। इस बात की इजाजत हम नही देगे। जो लोग बेरोजगार है जिनके घर मे कोई काम करने वाला नही है उनको काम मिले इस बात को हमने ध्यान मे रखा है और इसी ढग से हमने चुनाव किया है।

श्री रामजी राम (अकबरपुर) मैं एक जानकारी चाहता हू कि गावो मे उन लोगो को भी रोजगार मिला हुआ है जो 2 रुपये हर हलवाही करने के लिए मजबूर होते है और ऐसे लोगो को और काम करने मे रोका जाता है। तीन रुपये चार रुपये रोज का काम करने नही दिया जाता है। क्या ऐसे लोगो को भी काम दिया जायेगा ? मै अपने जिल की बात कह रहा हूँ।

श्री शेर सिह : अगर माननीय सदस्य इसके बारे मे अधिक सूचना द कि किस जगह पर ऐसा होता है तो उन सरकारो मे हम कहेगे कि उन लोगो को मौका देना चाहिए कि और काम कर सके।

मैं समझता हू कि यही प्रश्न विशेष रूप मे उठाए गये है जिनका जवाब मैंने दे दिया है।

---

18 25 hrs.

DISCUSSION RE . COLLAPSE OF A PORTION OF ROOF OF STEEL MELTING SHOP OF ROURKELA STEEL PLANT

SHRI J B. PATNAIK (Cuttack) : Mr. Chairman, I am beholded to you for giving me this opportunity to initiate this discussion on the Minister's statement. Much water has flowed in the river Jamuna between the day the roof collapsed of the